INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF HUMANITIES AND INTERDISCIPLINARY STUDIES
(Peer-reviewed, Refereed, Indexed & Open Access Journal)
DOI : 03.2021-11278686 ISSN : 2582-8568 IMPACT FACTOR : 7.560 (SJIF 2024)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षक शिक्षा

(National Education Policy 2020 and Teacher Education)

डॉ. गिरधारी लाल शर्मा
सहायक आचार्य,
शिक्षा विभाग,
जैन विश्वभारती संस्थान,
लाडनूं, राजस्थान - 341306
E-mail: Girdhari1976@gmail.com

DOI No. 03.2021-11278686 DOI Link :: https://doi-ds.org/doilink/04.2024-31246845/IRJHIS2404066

सारांश :

प्राचीन काल से ही भारतवर्ष में शिक्षा व्यवस्था का केन्द्र बिन्दु शिक्षक या गुरु रहा है, जिसके बिना जीवन का अर्थ समझ पाना संभव नहीं है। शिक्षक वास्तव में बच्चों के भविष्य को आकार देते हैं तथा छात्र और शिक्षक दोनों मिलकर हमारे समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अध्यापक की शिक्षा गुणवत्ता, भर्ती, पदस्थापना, सेवा शर्तें और शिक्षकों के अधिकारों की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में विभिन्न शिक्षा आयोगों एवं समितियों के सुझावों के जरिये अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार एवं परिवर्तन किया गया। इसमें 1964-66 के राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968) और राष्ट्रीय शिक्षक आयोग (चट्टोपाध्याय आयोग) 1983-85 ने सुधारात्मक सुझाब प्रस्तुत किये। अध्यापक शिक्षा के मामले में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 एक मील का पत्थर प्रतीत होती है, जो वर्तमान अध्यापक शिक्षा में सुधार और शिक्षण को आकार देने के लिए सभी आवश्यक कारकों का समावेश करती है। यह अपने बहुआयामी दृष्टिकोण से अध्यापक शिक्षा को पुनर्जीवित करने को समर्पित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अध्याय 15 में अध्यापक शिक्षा में सुधार से सम्बंधित प्रमुख प्रावधान वर्णित हैं। नई शिक्षा नीति ने बहुविषयक संस्थानों में चारवर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा लाने पर पर्याप्त जोर दिया है। इसके साथ ही विश्व विद्यालयों में शिक्षा विभाग खोलने पर भी बल दिया गया है। प्रस्तुत शोधपत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में शिक्षक शिक्षा के विभिन्न सुधारात्मक प्रावधानों एवं उनके प्रभाव का प्रस्तुतीकरण किया गया है।

मुख्य शब्दावली - *राष्ट्रीय शिक्षा नीति, शिक्षक शिक्षा, अध्यापक शिक्षा, शिक्षक*

मुख्य विषय वस्तु-

“शिक्षा करेगी नव युग का निर्माण, आने वाला समय देगा इसका प्रमाण।”

शिक्षा मानव-जीवन के सर्वांगीण विकास का सर्वोत्तम साधन है। प्राचीन शिक्षा-व्यवस्था मानव

को उच्च-आदर्शों की उपलब्धि के लिए अग्रसर करती थी और उसके वैयक्तिक, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन के सम्यक् विकास में सहायता करती थी। शिक्षा की यह व्यवस्था हर देश और काल में तत्कालीन सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन-सन्दर्भो के अनुरूप बदलती रहनी चाहिए।

जीवन में शिक्षा के महत्त्व को देखते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्तमान सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में व्यापक बदलावों के लिये **नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति** को मंजूरी दी है। करीब तीन दशक के बाद देश में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है। इससे पूर्व वर्ष 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी और वर्ष 1992 में इसमें संशोधन किया गया था। उम्मीद है कि यह शिक्षा नीति शिक्षा क्षेत्र में नवीन और सर्वांगीण परिवर्तनों की आधारशिला रखेगी।

विदित है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 को तैयार करने के लिये विश्व की सबसे बड़ी परामर्श प्रक्रिया आयोजित की गयी थी। जिसमें देश के विभिन्न वर्गों से रचनात्मक सुझाव माँगे गए थे।

प्राप्त सुझावों और विभिन्न शिक्षाविदों के अनुभव तथा **के. कस्तूरीरंगन समिति** की सिफारिशों के आधार पर **शिक्षा तक सबकी आसान पहुँच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही** के आधारभूत स्तंभों पर निर्मित यह नई शिक्षा नीति **सतत विकास** के लिये '**एजेंडा 2030**' के अनुकूल है और इसका उद्देश्य 21वीं शताब्दी की आवश्यकताओं के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज और वैश्विक महाशक्ति में बदलकर प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है।

लम्बे इंतजार और विचार-विमर्श के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को भारत सरकार द्वारा लाया गया है, जो भारत की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को देखते हुए एक स्वागत योग्य कदम हैवास्तव में ., स्वतंत्रता प्राप्ति के लगभग 70 वर्षों के बाद तक हम भारत की शिक्षा नीति को भारत की प्रकृति, संस्कृति एवं प्रगति के अनुरूप बनाने में विफल रहे हैंऐसे में , स्वतंत्रता के बाद पहली बार कोई शिक्षा नीति बनी है, जिसमें समग्रता में भारतीयता का समावेशन देखा जा सकता हदृष्टि इस . से'नई शिक्षा नति -2020' स्वयं में अद्वितीय है, 'नई शिक्षा नीति-2020' में कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं, जिनके व्यावहारिक अनुप्रयोग से भारत की शिक्षा को एक नया स्पर्श मिलेगा, जिसके बल पर हम भारतवर्ष को पुनः विश्वगुरु के पद पर आसीन करने की दिशा में अग्रसर होंगे।

यह हमारी आने वाली पीढ़ी को हमारे नैतिक मूल्यों, प्राचीन भारतीय विद्याओं, हमारी मातृभाषा के साथ तो जोड़ेगी ही, साथ में आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत का हमारा सपना भी साकार करेगी। हमारे गौरवशाली इतिहास को पुनर्जीवित करेगी। क्योंकि नई शिक्षा नीति की मुख्य विशेषता सबको सस्ती व अच्छी शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, कौशल विकास पर आधारित शिक्षा, रोजगार मुहैया कराने वाली शिक्षा हैं। समानता के साथ सबको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले हैं, यही इस शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य हैं।

शिक्षक शिक्षा सम्बन्धी सुधारात्मक प्रावधान -

राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रारूप के खंड संख्या 15 में शिक्षक शिक्षा से सम्बंधित प्रावधानों का उल्लेख किया किया गया है जो निश्चित ही शिक्षक शिक्षा की दशा व दिशा बदलने में महत्वपूर्ण साबित होंगे । राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षकों और शिक्षकों को सीखने की प्रक्रिया के केंद्र के रूप में पहचानती है। जैसा कि माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कल्पना की थी, नीति भारत के शिक्षकों को सशक्त बनाएगी और उनकी भर्ती, निरंतर व्यावसायिक विकास, सेवा शर्तों आदि के लिए विभिन्न सुधारों को सूचीबद्ध करेगी।

- एनईपी 2020 मानता है कि शिक्षकों को उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री के साथ-साथ अध्यापन में प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। 2030 तक, शिक्षक शिक्षा को धीरे-धीरे बहु-विषयक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में स्थानांतरित करने का प्रावधान है ।
- हमारे शिक्षकों के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बी.एड. होगी जो ज्ञान सामग्री और शिक्षाशास्त्र की एक श्रृंखला सिखाती है। इस डिग्री में स्थानीय स्कूलों में छात्र-शिक्षण के रूप में मजबूत व्यावहारिक प्रशिक्षण भी शामिल किया गया है ।
- 2 वर्षीय बी. एड. 4-वर्षीय एकीकृत बी.एड की पेशकश करने वाले समान बहु-विषयक संस्थानों द्वारा कार्यक्रम भी पेश किए जाएंगे। यह केवल उन शिक्षकों के लिए अभिप्रेत होगा जिन्होंने पहले ही अन्य विशिष्ट विषयों में स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली है।
- ये बी.एड. कार्यक्रमों को उपयुक्त रूप से 1-वर्षीय बी.एड के रूप में भी अनुकूलित किया जा सकता है। कार्यक्रम। उन्हें केवल उन लोगों के लिए पेश किया जाएगा जिन्होंने 4-वर्षीय बहु-विषयक स्नातक की डिग्री के समकक्ष पूरा किया है या जिन्होंने एक विशेष स्ट्रीम में मास्टर डिग्री प्राप्त की है।
- इसके अलावा, विशेष लघु स्थानीय शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम BITEs, DIETs और स्कूल परिसरों में भी उपलब्ध होंगे। ये पाठ्यक्रम स्थानीय कला, संगीत, कृषि, व्यवसाय, खेल, बढ़ईगीरी और अन्य व्यावसायिक शिल्प जैसे स्थानीय व्यवसायों, ज्ञान और कौशल को बढ़ावा देंगे। यह समग्र शिक्षा प्रदान करने की नीति के दृष्टिकोण के साथ भी संरेखित होता है।
- शिक्षक शिक्षा के लिए एक नया और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा, एनसीएफटीई 2021 तैयार किया जाएगा। राज्य सरकारों, केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों / विभागों और विभिन्न विशेषज्ञ निकायों सहित सभी हितधारकों के साथ चर्चा के बाद रूपरेखा विकसित की जाएगी और सभी क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराई जाएगी। NCFTE 2021 व्यावसायिक शिक्षा के लिए शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं का भी कारक होगा।
- शिक्षकों को शिक्षाशास्त्र के पहलुओं को चुनने में अधिक स्वायत्तता दी जाएगी, ताकि वे अपनी कक्षाओं में छात्रों के लिए सबसे प्रभावी तरीके से पढ़ा सकें। शिक्षक सामाजिक-भावनात्मक

सीखने पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे - किसी भी छात्र के समग्र विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू।

- शिक्षकों को उनकी कक्षाओं में सीखने के परिणामों में सुधार करने वाले शिक्षण के लिए नए दृष्टिकोण के लिए पहचाना जाएगा।
- शिक्षकों को आत्म-सुधार और अपने व्यवसायों में नवीनतम नवाचारों और प्रगति को सीखने के लिए निरंतर अवसर दिए जाएंगे। इन्हें स्थानीय, क्षेत्रीय, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं के साथ-साथ ऑनलाइन शिक्षक विकास मॉड्यूल सहित कई तरीकों से पेश किया जाएगा।
- प्रत्येक शिक्षक से अपने स्वयं के व्यावसायिक विकास के लिए प्रत्येक वर्ष कम से कम 50 घंटे के सीपीडी अवसरों में भाग लेने की अपेक्षा की जाएगी, जो उनके स्वयं के हितों से प्रेरित है। सीपीडी के अवसर, विशेष रूप से, मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता, सीखने के परिणामों के रचनात्मक और अनुकूली मूल्यांकन आदि के बारे में नवीनतम शिक्षाशास्त्र को व्यवस्थित रूप से कवर करेंगे।
- प्रत्येक शिक्षक चरण के भीतर कई स्तरों के साथ कार्यकाल, पदोन्नति और वेतन संरचना की एक मजबूत योग्यता-आधारित संरचना विकसित की जाएगी, जो उत्कृष्ट शिक्षकों को प्रोत्साहित करती है और पहचानती है। जैसा कि माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, "हम दिमाग को आकार देने और हमारे राष्ट्र के निर्माण में उनके योगदान के लिए मेहनती शिक्षकों के आभारी हैं।" NEP 2020 भारत को विश्वगुरु बनाने में सभी शिक्षकों के प्रयासों का सम्मान और सम्मान करेगा।
- शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन तथा समय-समय पर लिये गए कार्य-प्रदर्शन आकलन के आधार पर पदोन्नति।
- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद वर्ष 2022 तक 'शिक्षकों के लिये राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक' (National Professional Standards for Teachers- NPST) का विकास किया जाएगा।
- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा NCERT के परामर्श के आधार पर '**अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा' [National Curriculum Framework for Teacher Education-NCFTE)** का विकास किया जाएगा।
- शिक्षा नीति में वर्ष 2022 तक 'नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन' (NCTE) को टीचर्स के लिए एक समान मानक तैयार करने को कहा गया है। ये पैरामीटर 'नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स' कहलाएंगे। यह कार्य जनरल एजुकेशन काउंसिल के निर्देशन में पूरा करेगी।
- शिक्षा शास्त्र की सभी विधियों को शामिल करते हुए नए बीएड. कोर्स का सिलेबस तैयार

किया जायेगा। इसमें साक्षरता, संख्यात्मक ज्ञान, बहुस्तरीय अध्यापन और मूल्यांकन को विशेष रूप से सिखाया जाएगा। इसके अलावा 'टीचिंग मेथड' में टेक्नोलॉजी को खास तौर पर जोड़ा जाएगा। अयोग्य शिक्षक हटाए जाएंगे, स्तरहीन स्कूल बंद किए जाएंगे। पूरे भारत में एक जैसे शिक्षक और एक जैसी शिक्षा को आधार बनाकर इस समिति की सिफारिशों को लागू किया गया है।

नई शिक्षा नीति एवं चुनौतियां :

हालांकि नई शिक्षा नीति में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आज और आने वाले समय में विद्यार्थियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। जिसकी हर तरफ सराहना की जा रही है लेकिन इस शिक्षा नीति को ढंग से लागू करना भी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी।34 साल से चली आ रही एक ऐसी व्यवस्था को अचानक से बदल देना और लोगों द्वारा उसे स्वीकार कर ईमानदारी से उस पर अमन करना, यह सरकार और लोगों, दोनों के लिए काफी चुनौती भरा होगा।

- **राज्यों का सहयोगः** शिक्षा एक समवर्ती विषय होने के कारण अधिकांश राज्यों के अपने स्कूल बोर्ड हैं इसलिये इस फैसले के वास्तविक कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों को सामने आना होगा। साथ ही शीर्ष नियंत्रण संगठन के तौर पर एक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद को लाने संबंधी विचार का राज्यों द्वारा विरोध हो सकता है।
- **प्रवेश नीति एवं पाठ्यक्रम -** देश के विभिन्न राज्यों में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश की प्रक्रिया तथा पाठ्यक्रम में अत्यधिक विविधता विद्यमान है, इसे परिवर्तित कर समान पाठ्यक्रम एवं समान प्रवेश नीति बनाना और उसे लागू करना अत्यंत चुनोतिपूर्ण होगा।
- **शिक्षा का संस्कृतिकरणः** दक्षिण भारतीय राज्यों का यह आरोप है कि 'त्रि-भाषा' सूत्र से सरकार शिक्षा का संस्कृतिकरण करने का प्रयास कर रही है।
- **वित्तपोषणः** नई शिक्षा नीति के मुताबिक सरकार जीडीपी का 6% खर्च करने की बात कह रही है ।हालांकि 1986 के नई शिक्षा नीति में भी यही बात कही गई थी ।लेकिन वास्तविकता अलग है।2017-18 में भारत सरकार ने जीडीपी का केवल 2.7% ही शिक्षा पर खर्च किया । 2017-18 में शोध कार्य पर जीडीपी का 0.7% खर्च किया गया। तो खर्च के मामले में सरकार इतनी बड़ी छलांग कैसे लगा पाएगी। इस पर स्थिति साफ नहीं है।
- **मानव संसाधन का अभाव:** वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में कुशल शिक्षकों का अभाव है, ऐसे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के तहत प्रारंभिक शिक्षा हेतु की गई व्यवस्था के क्रियान्वयन में व्यावहारिक समस्याएँ हैं।
- **शिक्षकों की मानसिकता में परिवर्तन करना कठिन चुनौती होगी -** 34 साल पुरानी शिक्षा पद्धति के कारण एक ही ढर्रे में ढल चुके शिक्षकों की मानसिकता में परिवर्तन लाना बहुत कठिन चुनौती होगी। इसके लिए शिक्षकों की ट्रेनिंग का पूरा फ्रेमवर्क तैयार कर उन्हें जल्दी

से जल्दी ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी।क्योंकि शिक्षकों को इस नीति को समझने और फिर उसे अमल में लाने के लिए पहले उन्हें खुद आवश्यक ट्रेनिंग लेने की जरूरत पड़ेगी।

- **भारतीय उच्च शिक्षा व शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता बढ़ाना भी चुनौतीपूर्ण -** उच्च शिक्षा में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना भी चुनौतीपूर्ण हैं। इसके लिए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रोफेसरों की जवाबदेही तय करनी होगी और उनके अच्छे प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए कोई निश्चित व्यवस्था बनानी होगी। उच्च शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता को बढ़ाना भी चुनौतीपूर्ण है। क्योंकि बहुत कम भारतीय शिक्षण संस्थानों को शीर्ष विश्व रैंकिंग में जगह मिलती है।
- **अकादमिक क्रेडिट बैंक स्थापित करना होगा -** विश्वविद्यालयों में अकादमिक क्रेडिट बैंक स्थापित करना आवश्यक होगा जिससे अगर कोई विद्यार्थी एक संस्थान से दूसरी संस्थान में स्थानांतरित होगा, तो उसके पूर्व के अर्जित क्रेडिट अंक आगे जोड़े जा सकें।
- **मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम -** उच्च शिक्षा में "मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम" किया गया है। और छात्रों को एक वर्ष में सर्टिफिकेट और दो वर्ष में डिप्लोमा दिया जायेगा। नौकरी या अन्य जगहों पर इनकी उपयोगिता भी निश्चित करनी होगी। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में इसे लागू करना अपने आप में चुनोतिपूर्ण होगा।
- **मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम** - उच्च शिक्षा में "मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम" किया गया है। और छात्रों को एक वर्ष में सर्टिफिकेट और दो वर्ष में डिप्लोमा दिया जायेगा। नौकरी या अन्य जगहों पर इनकी उपयोगिता भी निश्चित करनी होगी। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा इसका विरोध होना भी निश्चित है ।

निष्कर्ष -

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अनेक ऐसे सकारात्मक सुझाव हैं जो भारत को शिक्षा के क्षेत्र में नए मानक स्थापित करने में मदद करेंगे। शक्षक शिक्षा की दशा व दिशा को परिवर्तित कर यह नीति गुणवत्तापूर्ण शिक्षक तैयार करने में सफल होगी। लेकिन इसकी सफलता के लिए आवश्कता है समग्र प्रयास की । इस नीति को आवश्कता है सम्पूर्ण जन समर्थन की , जिसमे भाषा, प्रान्त या मजहब की कोई दीवार ना हो । समग्रता में कहा जाए तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से भारत की शिक्षा में भारतीयता का सही अर्थों में प्रादुर्भाव हुआ है सैद्धांतिक और व्यावहारिक शिक्षा के मध्य, भौतिकता और आध्यात्मिकता के मध्य, परंपरागत मूल्यबोध और आधुनिक तकनीक के मध्य समन्वय की एक सुंदर चेष्टा इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में देखी जा सकती है. आवश्यकता है, इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सम्यक तरीके से व्यावहारिक धरातल पर उतारने की।

सन्दर्भ -

1. सोडानी, कैलाश (2021). राष्ट्रीय शिक्षा निति : 2020 - क्रियान्वयन, एपेक्स पब्लिशिंग हाउस

2. National Education Policy 2020 document, Govt. Of India
3. National and international webinars and FDPs organized by different universities and colleges all over India on NEP-2020
4. https://www.education.gov.in
5. https://www.dristiias.com
6. https://www.hindiswaraj.com
7. https://www.education.gov.in
8. https://www.hindi.rajras.in
9. https://www.prindia.org
10. https://www.pmmodiyojana.in